International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2020; 2(2): 72-74
Received: 03-06-2020
Accepted: 13-08-2020

डां. श्रीमती संगीता सिंघल
एसोसियट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, सनातन धर्म महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डां. श्रीमती संगीता सिंघल
एसोसियट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, सनातन धर्म महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत

ग्रामीण विकास में नाबाड़ की भूमिका

डां. श्रीमती संगीता सिंघल

DOI: https://doi.org/10.22271/multi.2020.v2.i2a.140

प्रस्तावना

भारत गांवों का देश है। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि न केवल ग्रामीण जनसंख्या का जीविकापार्जन का साधन है बल्कि अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार भी है। इसीलिए कृषि को भारतीय अर्थतंत्र का आधार कहा जाता है। गांधीजी के अनुसार भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी, औद्योगिक केन्द्रों के विकास से नही, बल्कि मुख्य रूप से गांवो के विकास से नही है। स्वतंत्रता के बाद मुख्य रूप से विकास को बढावा देने के लिए अर्थ व्यवस्था के विनिर्माण और व्यापार क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। भारत में आबादी का एक बडा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और ग्रामीण विकास में कृषि वित्त की उल्लेखनीय भूमिका रही है। इसीलिए ग्रामीण वित्तीय गतिविधियों को विकसित करना महत्वपूर्ण है। जनसंख्या का 60 प्रतिशत भाग, कृषि उत्पादों पर निर्भर करता है लेकिन फिर भी किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो की स्थिति अच्छी नही है। ग्रामीण जनसंख्या को अपना जीवन यापन करने के लिए ऋण और सही दिशा की आवश्यकता होती है, भारत में जोत का आकार छोटा होने के कारण उनकी आय बहुत कम है, अतः उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर रहना पडता है। इसीलिए सरकार ने ग्रामीण वित्तीय गतिविधियों को विकसित करने हेतु ही नाबार्ड की स्थापना की थी। नाबार्ड की स्थापना से पहले त्ठप् रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया भारतीय अर्थ व्यवस्था को ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु शीर्ष निकाय था। नाबार्ड की भूमिका मुख्य रूप से कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की भूमिका का ही विस्तार है।

कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक NABARD

कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिलप और ग्रामीण शिल्पों के उन्नयन और विकास के लिए ऋण प्रवाह सुविधाजनक बनाने के अधिदेश के साथ नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को एक शीर्ष विकासात्मक बैंक के रूप में स्थापित किया गया। इसे ग्रामीण क्षेत्रों से अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने, एकीकृत और सतत् ग्रामीण विकास को बढावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि सुनिश्चित करने का भी अधिदेश प्राप्त है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक ऐसा बैक है जो ग्रामीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनकी जीवन स्तर सुधारने के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना 100 करोड प्रारम्भिक पूंजी के साथ की गई थी।

कृषि और ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक के कार्य

- ग्रामीण साख के क्षेत्र में कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है।
- अपने कृषि साख विभाग के माध्यम से वह सरकारी क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखता है।
- मौसमी कृषि कार्यो (फसल ऋणों) के लिए, उर्वरकों की खरीद व वितरण के लिए तथा सरकारी चीनी फैक्ट्रियों की कार्यशील पूंजी के लिए वह सरकारी बैंकों को अल्पकालीन ऋण (18 महीनों की अवधि के लिए) प्रदान करता है।
- यह निर्धारित कृषि उद्देश्यों, परिष्करण समितियों (च्तवबमेपदह॑वबपमजपमे) के शेयरों की खरीद तथा प्राकृतिक विपदायों से ग्रस्त इलाकों में अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने के लिए यह राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मध्यकालीन ऋण (18 महीने से 7 वर्ष तक के लिए) प्रदान करता है।
- कृषि में बडे निवेश कार्यो के लिए यह राज्य सहकारी बैंको, भूमि विकास बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा व्यापारिक बैकों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण (अधिक से अधिक 25 वर्षो के लिए) प्रदान करता है।
- केन्द्रीय व राज्य सहकारी बैंको तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निरीक्षण की जिम्मेदारी कृषि और ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक को दी गयी है।
- सहकारी साख संस्थाओं की शेयर पूंजी में योगदान देने के लिए यह राज्य सरकारों को ऋण के रूप में दीर्घकालीन सहायता (अधिकतम अवधि 20 वर्ष) प्रदान करता है।

- कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक अनुसंधान व विकास फण्ड रखता है ताकि कृषि व ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जा सके, तथा विभिनन इलाकों की आवश्यकताओं के अनुसार परियोजना का बनाया जा सके।

नाबार्ड का योगदान
नाबार्ड ने वित्तीय, विकासात्मक एवं पर्यवेक्षण कार्य के संदर्भ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लगभग सभी परिपेक्ष्य को स्पर्श किया।

वित्तयी योगदान
नाबार्ड ने 2003–04 के दौरान अल्पकालीन उधार के रूप में 8820 करोड रूपये की ऋणों की स्वीकृति दी और ऋण मौसमी कृषि, क्रियाओं को बैंक दर से 3 प्रतिशत नीची रियायती दर पर दिए गए। 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन कमजोर वर्गो को उधार की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड ने बैंकों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि अपने अल्पकालीन ऋणों का एक निश्चित प्रतिशत छोटे तथा सीमान्त किसानों और अन्य आर्थिक दृषि से पिछडे वर्गो को उपलब्ध कराएंगें।

पुनर्वित्त–लघु अवधि ऋण
कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंको तथा ग्रामीण कृषि साख समितियों को पुनर्वित सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2010–11 के दौरान नाबार्ड ने सहकारी संस्थाओं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य सरकारों की कुल 35,273/– करोड रूपये की ऋण सहायता उपलब्ध करायी।

ग्रामीण आधार संरचना विकास फण्ड (RIDF)
वर्ष 1995–96 से 2000 करोड रूपये का पहला ग्रामीण आधार संरचना विकास फण्ड स्थापित किया गया। (RIDF) के अन्तर्गत कई उद्देश्यों के लिए ऋण दिये ऋण दिये जाते है जैसे सिंचाई परियोजनाऐं, जल संभर, प्रबन्धक, ग्रामीण सडकों व पुलों का निर्माण इत्यादि। RIDF के अधीन नाबार्ड ने 1995–96 से 2006–07 के बीच 35720/– रूपये की जमा राशि गतिमान की। भारत में निर्धन व्यक्तियों को संगठित वित्तीय सैक्टर के दायरे में लाने का काम लघु वित्त योजनाऐं कर रही है इस संदर्भ में नाबार्उ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह सहायता संगठनों एवं बैंकों का लिकेंज कार्यक्रम (SHG-Bank Linkage Programme) लघु वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास बनकर उभर रहा है।
इस बात से स्पष्ट है कि गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में लघु वित्त की प्रभावी भूमिका है। वर्ष 1992 में नाबार्ड ने स्वंय सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम (Self Help Camp Bank Linkage Programme SHG-BPL) की शुरूआत की थी। इसमें वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 23 लाख स्वंय सहायता समूहों ने बैंक क्रेडिट लिंक्ड रजिस्टर किये।

दीर्घकालीन सिंचाई कोष (LTIF): नाबार्ड के तहत दीर्घकालीन सिंचाई कोष की स्थापना वर्ष 2016–17 के केन्द्रीय बजट में की गई थी। इस बजट में 99 सिंचाई परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए प्रारम्भिक राशि 20,000 करोड रूपये की घोषणा की गई थी।

गोदाम अवसंरचना कोष (Warehouse Infrastructure Fund-WIF): केन्द्र सरकार ने वर्ष 2013–14 में नाबार्ड के साथ 5000 करोड रूपये की धनराशि के साथ WIF की स्थापना की, जो देश में कृषि वस्तुओं के लिए सांइटिफिक वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आवश्यक ऋण उपलब्ध कराता है।

- नाबार्ड ने बहु–सेवा केन्द्र संचालित करने के लिए उत्पादक संगठनों (Producer Organizations-POs) एवं प्राथमिक कृषि ऋण (Primary Agriculture Credit Societies-PACS) को वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए 50 करोड की प्रांरभिक राशि के साथ उत्पादक संगठन विकास कोष (PODF) की स्थापना की।
- उत्पादक संगठन (PO) एक विधिक संस्था है, जिसका गठन प्राथमिक उत्पादकों अर्थात किसान, दुग्ध उत्पादक, मछली उत्पादक, बुनकर, ग्रामणी शिल्पकार, शिल्पी आदि द्वारा कियाजाता है। उत्पादक संगठन एक उत्पादक कम्पनी, कॉ–ऑपरेटिव सोसायटी या कोई वैधानिक संरचना हो सकती है जो सदस्यों के बीच का बंटवारा करती है।
- प्राथमिक कृषि समिति एक आधार इकाई है एवं भारत में ऋण देने वाला सबसे छोटा को–ऑपरेटिव संस्थान है। यह जमीनी स्तर (ग्राम पंचायत और ग्रामीण स्तर) पर कार्य करता है। यह किसानों को टर्म लोन के रूप में ऋण प्रदान करता है और कृषकों से राशि की वसूली फसल कटाई के बाद करता है।

विकासात्मक योगदान
- **किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड–** 1988 में फसल ऋण प्रदान करने के लिए नाबार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत की थी। अगस्त 2012 के अन्त में 9.54 करोड किसान बीमा कार्ड जारी किये गये।
- **रूपये किसान कार्ड–** नाबार्ड अपने सभी किसानों, ग्राहकों को ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से रूपे किसान कार्ड प्रदान करके प्रौद्योगिकी क्रान्ति में सबसे आगे है।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर अंब्रेला कार्यक्रम (UPNRM)
UPNRM की शुरूआत वर्ष 2007 में हुई। यह ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने व्यवसाय के अवसर पैदा करने के साथ–साथ अपने प्राकृतिक संसाधनों के सतत् उपयोग हेतु ग्रामीण समुदाय को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है।
- **ईशक्ति कार्यक्रमः**–15 मार्च 2015 को स्वंय सहायता समूह (SHGs) के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से ई–शक्ति कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था।
- **कौशल विकासः** युवाओं में उद्यमी संस्कृति को बढाना देना एवं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में गैर–कृषि क्षेत्रों से संबंधित उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस प्रकार के कार्यो को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड तीन दशक से रणनीतिक रूप से कार्य कर रहा है।
- **मार्केटिंग पहलः** नाबार्ड ग्रामीण शिल्पकारों एवं उत्पादकों को मार्केटिंग अवसर उपलब्ध कराने के लिए देश भर में आयोजित प्रदर्शनियों में उन्हें भागीदारी के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
- **इनक्यूबेशन सेंटरः** देश में नवाचारों को व्यवसायिक बनाने, कृषि उद्यमिता को आकार देने ओर एग्री इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए नाबार्ड को चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार एवं तमिलनाडू कृषि विश्वविद्यालय, मुदैर को 23.99 करोड रूपये की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की।

चुनौतियाँ
- भारतीय रिजर्व बैंक के उत्तराधिकारी के रूप में नाबार्ड अपने मूल जनक संस्थानों की कार्य संस्कृति, प्रकृति और विकास ओरियंटेशन को साझा करता है।

- नाबार्ड की बाजार उधारी इसके संसाधनों के 80 प्रतिशत तक होने की इसकी वित्तपोषण की लागत बढ गई है।
- उत्तरी–पूर्वी राज्यों को नाबार्ड के क्रेडिट फंड का बहुत कम हिस्सा मिल रहा है। उत्तरी–पूर्वी राज्यों को क्रेडिट का 1 प्रतिशत ही मिलता है। ये राज्य मनी–लैंडर्स के जाल में फंसाने वाले किसानों के परिदृश्य के संदर्भ में अग्रणी है।
- उग्र प्रभावित राज्यों में बैंकों की पहुंच कम है एंव बैकों को इन राज्यों की ओर अपना कदम बढाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत में 75 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि पर निर्भर है। ग्रामीण अवसरंचना निवेश से ग्रामीण लोगो की सामाजिक–आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायता मिलती है। जिससे कि उनकी जीवन गुणवत्ता एवं आय में वृद्धि होती है। नाबार्ड भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षमता निर्माण एवं नाबार्ड से अनेक कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास में योगदान दिया, परन्तु इसके उपरान्त भी आज भारत में ग्रीमण विकास में अपेक्षित सुधार नही हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षा के कारण, उन्हें योजनाओं का ज्ञान ही नही हो पाता है और वे चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नही उठा पाते है। अब नाबार्ड ने योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए है अतः इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण विकास करने में सहायता मिलेगी और हम विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण कर पायेंगें।

संदर्भ

1. दत्त सुन्दरम ''भारतीय अर्थव्यवस्था''
2. वी.के. पुरी ''भारतीय अर्थव्यवस्था''
3. डा. जे. पी. मिश्रा – भारतीय आर्थिक समस्याऐं
4. टी. आर. जैन – भारतीय आर्थिक समस्याऐं
5. https://www.drishtias.com
6. https://www.nabard.org
7. https://wikipedia.org
8. https://sarkariguider.in